



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

# बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (शा०)

(सं० पटना 31) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

### अधिसूचना

5 नवम्बर 2014

सं० 22 / नि०सि०(वीर०)-०७-०८ / २००८ / १६२८—श्री अरविन्द कुमार रिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, पश्चिमी तटबंध प्रमण्डल, कुनौली, वीरपुर द्वारा वर्ष 2002-03 में पश्चिमी कोशी तटबंध के 2.25 कि० मी० एवं 9.00 कि० मी० पर निर्मित स्पर पर मेसर्स शांभवी कन्सट्रक्शन द्वारा तथाकथित रूप से कराये गये बाढ़ संधार्षात्मक कार्य का विपत्र तैयार करने एवं प्रपत्र 24 तैयार कर कार्यपालक अभियन्ता को भेजने से संबंधित बरती गयी अनियमितता के लिए उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र—“क” गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 398 दिनांक 22.5.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा दोनों स्परो के कटाव होने के उपरान्त बाढ़ संधार्षात्मक कार्यों के लिए भुगतान किये जाने के संदर्भ में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

1. दिनांक 22.11.05 को अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में अदेयता समिति की बैठक में संवेदक के अदेयता को मान्य पाया गया तथा भुगतान हेतु अनुशंसा की गई।

2. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के उप सचिव द्वारा एम० जे० सी० सं०-२०२३ / ०६ दिनांक 20.08.07 को माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर “शपथ पत्र” दाखिल कर यह प्रतिवेदित किया गया है कि शांभवी कन्सट्रक्शन को भुगतान करने का निर्णय विभाग द्वारा सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए राज्य सरकार से आदेश प्राप्त कर लिया गया है।

अतः इस संबंध में किसी भी पदाधिकारी पर कार्रवाई न्यायोचित नहीं होता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त सारे तथ्यों एवं साक्ष्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदित किया गया है कि विभाग द्वारा शांभवी कन्सट्रक्शन को भुगतान करने का निर्णय हरेक स्तर पर सभी विन्दुओं की पूरी छानबीन कर वित्त विभाग एवं मुख्य सचिव—सह—परामर्शी (राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के कारण) द्वारा दिये गये स्वीकृत्यादेश के आलोक में किया गया है तथा इसके लिए आरोपित पदाधिकारी पर लगाये गये आरोप बेवजह एवं निराधार है।

अन्त में संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष में कहा गया है कि आरोपित पदाधिकारियों के स्पष्टीकरण एवं समर्पित बचाव बयानों की समीक्षा की गई एवं उनके विरुद्ध आरोप “क” एवं “ख” स्थापित नहीं होता है।

उक्त वर्णित स्थिति में समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को आरोप मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश श्री अरविन्द कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सतीश चन्द्र झा,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 31-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>